साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 4-10 जुलाई 2022, वर्ष-8, अंक-13

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा- समरस पंचायतों में नशामुक्ति का अभियान चलाया जाए

नशामुक्त गांवों को दो लाख रुपए इनाम देगी मप्र सरकार

जागत गांव हमार। भोपाल

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि प्रदेश में नशामुक्त गांवों को दो लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। चौहान ने मुख्यमंत्री निवास परिसर में निर्विरोध निर्वाचन द्वारा समरस पंचायतों का गठन करने वाले प्रतिनिधियों के अभिनंदन समारोह के दौरान कहा कि प्रदेश में वर्तमान में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 630 सरपंच, 157 जनपद पंचायत सदस्य और एक जिला पंचायत सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सीएम ने कहा कि इन पंचायतों को समरस पंचायत कहा गया है। समरस पंचायतों में नशामुक्ति का अभियान चलाया जाए। नशामुक्त गांव को विशेष रूप से दो लाख का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। किसी भी पंचायत में सरपंच का निर्वाचन निर्विरोध रूप से होने पर पांच लाख रुपए, सरपंच पद के लिए वर्तमान और पिछला निर्वाचन निरंतर निर्विरोध होने पर सात लाख तथा सभी पंच और सरपंच निर्विरोध निर्वाचित होने पर सात लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार पंचायत में सरपंच एवं पंच के सभी पदों पर महिलाओं का निर्वाचन होने पर पंचायत को 12 लाख रुपए और पंचायत में सरपंच एवं पंच के सभी पदों पर महिलाओं का निर्वाचन निर्विरोध होने पर पंचायत को 15 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

समरस पंचायत में बेटियों का बढ़े मान

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्राम को नशा मुक्त बनाने के लिए आपसी बातचीत और विभिन्न प्रेरणास्पद गतिविधियों से वातावरण निर्मित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समरस पंचायतों सहित सभी पंचायतों में बेटियों का मान, सम्मान और इज्जत बढ़े और बेटा-बेटी को बराबर माना जाए।

पंचायत में न रहे कुपोषण

सीएम ने कहा कि मां, बहन, बेटी की तरफ गलत नजर से देखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि समरस पंचायतों को अपने काम से पूरे देश में उदाहरण प्रस्तुत करना है। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करें कि हमारी पंचायत में कोई बच्चा कुपोषित नहीं रहे।

मंडला-डिंडोरी से होगी शुरुआज, सबसे पहले बैगाओं को मिलेंगी गाय

आदिवासियों को 75% सब्सिडी पर दो गाय

-साहीवाल, थारपारकर, गिर सहित अन्य नस्लों को गाय दी जाएंगी

जागत गांव हमार। भोपाल

अब मध्यप्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि दुधारू गाय खरीदने सरकार सब्सिडी देने जा रही है। इसके लिए नई योजना का सरकारी खाका भी तैयार कर लिया गया है। योजना लॉन्च होते ही इसका श्रीगणेश आदिवासियों से होगा। राज्य के पशुधन विकास निगम के मुताबिक 75 फीसदी सब्सिडी पर दो गायें दी जाएंगी। दरअसल, राज्य सरकार आदिवासियों पर विशेष फोकस कर रही है। इसी कड़ी में सरकार नई योजना ला रही है। इसमें आदिवासियों को 75 फीसदी सब्सिडी पर दो गाय दी जाएंगी। ताकि उनका जीवन स्तर सुधरे और वे दूध उत्पादन से जुड़ सकें। पशुपालन विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। योजना की शुरुआत में सबसे पहले बैगा आदिवासियों को गायें मिलेंगी। शुरुआत डिंडोरी, मंडला से होगी। इसके बाद योजना में सहरिया और भारिया जनजातियों को जोड़ेंगे।

गाय पालने की ट्रेनिंग भी मिलेगी- साहीवाल, थारपारकर, गिर सहित अन्य नस्लों को गाय दी जाएंगी। हितग्राहियों को गाय पालने की ट्रेनिंग भी मिलेगी। दो गायों के साथ एक बछिया भी दी जाएगी। जिस गाय की बछिया होगी वह दूध दे रही होगी, जबकि दूसरी गाय प्रेग्नेंट रहेगी। इस तरह से हितग्राही को लगातार दूध की उपलब्धता रहेगी। गिर गाय एक दिन में 10 से 15 लीटर तक दूध दे देती है।

डेयरी व्यवसाय से जुड़ने की राह भी मिलेगी

मप्र में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और मेहनतकश ग्रामीण किसानों का जीवन स्तर सुधारने की दिशा में सरकार ने एक कदम और बढ़ाया है। ऐसे किसान जो अभी तक पैसों की तंगी और खेती के लिए खुद की जमीन न होने का रोना रोते थे, उनको डेयरी व्यवसाय से जुड़ने की राह भी मिलेगी। पशुपालन विभाग द्वारा तैयार किए प्रस्ताव के मुताबिक सब्सिडी पर दो गाय दी जाएंगी।

आचार्य विद्यासागर और नंदी शाला

प्रदेश में मवेशी पालन के लिए अभी दो योजनाएं आचार्य विद्यासागर और नंदी शाला योजना चल रही हैं। आचार्य विद्यासागर योजना में 8.50 लाख रुपए लोन दिया जाता है। वहीं नंदी शाला योजना में सरकार 22500 रुपए में कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड उपलब्ध कराती है।

दो गाय की कीमत करीब सवा लाख रुपए होगी। इसमें गायों की मूल कीमत 90 हजार रुपए, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च 8 हजार रुपए, दवाओं का 2 हजार रुपए, चारे का 18 हजार रुपए तो इंश्योरेंस का 7500 रुपए शामिल है। इसमें हितग्राही को करीब 31 हजार रुपए देना होंगे। शेष राशि अनुदान में मिलेगी। अगस्त से योजना शुरू की जाएगी।

डॉ. एचबीएस भदौरिया, एमडी, पशुधन विकास निगम

गाय से मिलेगा 10-15 लीटर दूध

सब्सिडी पर मिलने जा रही कई नस्लों की गायों की दूध देने की अलग-अलग क्षमता होती है। यह हितग्राही द्वारा गायों के पालन-पोषण पर भी निर्भर करेगा। एक अनुमान के मुताबिक औसतन गिर गाय प्रतिदिन दस से पंद्रह लीटर तक दूध दे देती है। इसी तरह साहीवाल गाय प्रतिदिन इतना ही दूध देती है। एक गाय दुग्धकाल के दौरान औसतन करीब 2300 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। साहीवाल, थारपारकर, गिर जैसी नस्लों की गायों को खूबियों के चलते वैज्ञानिक सबसे अच्छी देशी दुग्ध उत्पादक गाय मानते हैं।

1000 सदस्य और कम से कम तीन करोड़ वार्षिक व्यवसाय को बनाया आधार

मप्र में सहकारी समितियों का अब होगा परिसीमन

-सहकारिता विभाग ने जिलों को पत्र लिखकर कार्रवाई करने के दिए निर्देश

जागत गांव हमार। भोपाल

मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के लिए प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का परिसीमन किया जाएगा। इसमें समितियों के क्षेत्र नए सिरे से निर्धारित होंगे। जिस गांव के पास जो समिति होगी, उससे ही किसानों को जोड़ा जाएगा। सरकार की इस कवायद को करने के पीछे मंशा समितियों की आर्थिक सेहत सुधारने की है। दरअसल, कई समितियों की स्थिति अच्छी नहीं है। इसे देखते हुए आर्थिक रूप से कमजोर समितियों को अन्य समितियों से संबद्ध किया जाएगा। प्रदेश में 4548 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति हैं। इनसे 50 लाख से अधिक किसान जुड़े हैं। समितियां किसानों को ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराने के साथ खाद-बीज का वितरण, गेहूं व धान का उपार्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण का काम करती हैं। अब इन्हें सशक्त बनाने के लिए अन्य कार्यों से भी जोड़ा जा रहा है। सहकारी नीति में इसके लिए प्रावधान किए जा रहे हैं।

नए सदस्य बनाने के निर्देश

ऐसी समितियां, जिनका वार्षिक व्यवसाय तीन करोड़ से कम है, उन्हें नए सदस्यों को जोड़ने के साथ अन्य गतिविधियां संचालित करने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही समितियों की आय बढ़ाने के लिए उचित मूल्य की राशन दुकानों को बहुद्देश्यीय दुकानों में परिवर्तित करने, गोदाम बनाने, प्रसंस्करण केंद्र संचालित करने सहित अन्य कार्यों से जोडा जा रहा है। इसके लिए कुछ समितियों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भी तैयार करवाए गए हैं। इन्हें कृषि अधोसंरचना निधि के माध्यम से बैंकों से ऋण दिलाया जाएगा।

समिति के परिसीमन के लिए जो मापदंड तय किए हैं, उसमें समिति के कार्यक्षेत्र में कम से कम पांच हजार हेक्टेयर भूमि, तीन करोड़ रुपए का वार्षिक व्यवसाय और कम से कम एक हजार सदस्य होने चाहिए। इस आधार पर प्रस्ताव बनेंगे और समितियों के क्षेत्र निर्धारित होंगे।

अरविंद सिंह सेंगर, संयुक्त पंजीयक, सहकारिता

कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ द्वारा दी गई किसानों को समयमाकी जानकारी

खरीफ फसल की नर्सरी तैयार करने का कृषि वैज्ञानिकों ने पढ़ाया पाठ

जागज गांव हमार। टीकमगढ़

कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. बीएस किरार, डॉ. एसके सिंह, डॉ. आरके प्रजापति एवं जयपाल छिगारहा द्वारा खरीफ में सब्जी उत्पादन पर किसानों को सम-समायिकी सलाह दी जा रही है। हमारे देश में कुछ सब्जियों की बोवनी सीधे खेत में की जाती है जैसे - भिंडी, लोबिया, खीरा, पालक, गाजर, मूली, लौकी, तोरई, करेला, कुम्हड़ा इत्यादि। कुछ सब्जियों की लताए, कंद एवं बल्व जैसे-परवल, कुंदरू, सूरन तथा कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनकी पहले पौध तैयार करनी पड़ती हैं। उसके लगभग 28 से 30 दिन के बाद उनका रोपण किया जाता है जैसे - बैगन, मिर्च, टमाटर, पत्तागोभी, फूलगोभी, गांठगोभी इत्यादि।

नर्सरी पर निर्भर अच्छी खेती- किसान की अच्छी खेती उसके नर्सरी पर ही निर्भर करती है। सब्जियों की स्वस्थ पौध तैयार करने में किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे की एक अच्छे एवं स्वस्थ पौध खेत में रोपण के समय तैयार हो सके कुछ सब्जियां जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च, गोभी एवं प्याज के बीज इतने छोटे होते है कि उनकी बोवनी सीधे खेत में करना और उनकी अच्छी तरह देखभाल करना अत्यन्त कठिन हो जाता है। अत: इसके लिए पहले बीज को पौधशाला में बोवनीकर पौध तैयार कर लेते हैं। उसके बाद उसका रोपण करते हैं।

अच्छे से तैयार करें खेत की मिट्टी

पौधों की बुवनी सीधे खेत में करने के लिए पूरे खेत की मिट्टी को बहुत ही अच्छी तरह तैयार करना पड़ेगा जैसा कि हम पौधशाला के लिए करते हैं जो कि संभव नहीं है। इसमें लागत अधिक लगती है। कभी-कभी वर्षा ऋतु में लगातार कई दिनों तक वर्षा होती रहती है। जिससे खेतों में कार्य करने का मौका नहीं मिलता। ऐसी विषम परिस्थितियों में हमें नर्सरी जो कि वर्षा आदि से सुरक्षित स्थान पर लगाते हैं और वर्षा समाप्त होने पर जब मौसम साफ हो जाए तो हम उसे खेत में रोप सकते हैं। सब्जियों की पौध उगाकर इसे बाजार या किसानों को उचित मूल्य पर विक्रय कर इसे व्यवसायिक रूप दिया जा सकता है।

सब्जियों की स्वस्थ नर्सरी के अहम पहलू

बीज उन्नतशील प्रजाति का हो

चयनित स्थान पर सूर्य का प्रकाश एक समान रूप से उपलब्ध हो। जंगली एवं पालतू पशुओं के नुकसान के प्रति सुरक्षित हो। पौधशाला के लिए ऐसे स्थान का चयन करें जहां वर्षा का पानी न रुकता हो तथा आसपास के क्षेत्र से स्थान ऊंचा हो। सिंचाई की उचित व्यवस्था हो जिससे समय-समय पर उनकी सिंचाई की जा सके। बीज उन्नतशील प्रजाति का हो, बीज विश्वसनीय संस्था से क्रय किया हो।

मिट्टी का शोधन अवश्य करें

पौधशाला की भूमि को फावड़े या कुदाल की सहायता से खुदाई करें। यदि मिट्टी ठीक न हो तो आवश्यकतानुसार कम्पोस्ट व रेत मिलाकर मिट्टी को पौधशाला के योग्य बना लें। पौधशाला वाली मिट्टी से खरपतवार साफ करके भुरभुरी बना लें। मिट्टी का शोधन अवश्य करें। इसके लिए मृदा सौर्यीकरण या कैप्टान या थीरम 5 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से उपचारित करें। बीज बोने के लिए कम से कम 20 सेमी ऊंची क्यारियां बनाएं।

छायादार शेड का प्रयोग करें

क्यारियों की लंबाई लगभग 5 से 7 मीटर तक रख सकते हैं, लेकिन इनकी चौड़ाई 1 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। बीजों की बोवनी हमेशा कतारों में 5 सेमी की दूरी पर करें। बीजों की बोवनी के बाद बीजों को रेत, कम्पोस्ट एवं मिट्टी से ढक देना चाहिए। बीज को ढकने के बाद क्यारी को धान की पुआल से ढक दें। बीज के अंकुरण के बाद पलवार को तुरन्त हटा लें। शरद ऋतु में पौधों को पालीहाऊस या पालीथीन की झोपड़ी में उगाएं। अधिक धूप से बचाव के लिए 1 मी. ऊंचाई पर छायादार शेड का प्रयोग करें।

-मेडिकैप्स विवि में कृषि संकाय के विद्यार्थियों ने की पहल

इंदौर में जीरो बजट प्राकृतिक कृषि पद्धति का श्रीगणेश

जागत गांव हमार, इंदौर।

जेजबीएनएफ (जीरो बजट प्राकृतिक खेती) हमारे देश में कई किसानों द्वारा अपनाई गई कृषि पद्धति है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा भी देश में किसानों की आमदनी दोगुनी करने के उद्देश्य से प्रोत्साहित किया जा रहा है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती के तहत किसानों क खेती करने के लिए किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, जबकि बहुत कम लागत में किसान अपने आस-पास की प्राकृतिक स्त्रोतों जैसे प्राकृतिक खाद, जीवामृत, बीजामृत, आन्चादन (मलिचंग) और व्हापास आदि प्रमुख स्तंभों की मदद से खेती कर सकते हैं। मेडिकैप्स विश्वविद्यालय में लगातार चार वर्षों से कृषि संकाय के छात्रों द्वारा जैविक कृषि का अभ्यास किया जा रहा है। छात्रों को मार्गदर्शन के लिए कृषि संकाय के डीन डॉ. एसडी उपाध्याय एवं डॉ. कुंदन सिंह विभागाध्यक्ष कृषि संकाय द्वारा समय-समय पर छात्रों को प्रोत्साहन एवं सुविधा उपलब्ध करवाते रहते हैं।

कम लागत में ज्यादा पैदावार

कृषि संकाय के शिक्षक डॉ. सुहाना पुरी गोस्वामी (मृदा एवं विज्ञान) ने छात्रों को जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कृषि पद्धति से मृदा को होने वाले फायदे जैसे मृदा में सुक्ष्मजीवों की गतिविधि बढ़ाने की उपयोगिता समझाते हुए फसलों की पैदावार में कम लागत के लिए एक प्रायोगिक दिशा बताया है। मेडिकैप्स विवि के अंतिम वर्ष मे अध्ययनरत छात्रों में आदित्य पाटीदार, मनोज पाटीदार, रितिक राठौर, निखिल पाटिदार, अभय पाटिदार, आकाश पात्रा, दीपेन्द्र एवं मधुसूदन यादव की टीम वर्क ने मूंग की खेती जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कृषि पद्धति के माध्यम से अपने एक्सपिरियंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत अपने कोआर्डिनेटर उपासना मिश्रा के मार्गदर्शन में कार्य संपन्न किया।

रसायन मुक्त कृषि का एक अभ्यास

जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग मूल रुप से महाराष्ट्र के एक किसान सुभाष पालेकर द्वारा विकसित रसायन मुक्त कृषि का एक अभ्यास है। यह विधि एक तरह से पारंपरिक भारतीय कृषि पद्धति का रूप है। कृषि में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मेडिकैप्स विवि के कुलाधिपति आरसी मित्तल एवं कुलपति प्रो. डीके पटनायक मार्गदर्शक के रूप में सदैव प्रयासरत रहते हैं। समय-समय पर ओएसडी, पलाश गर्ग, प्रति कुलपति प्रोफ. डी. के पांडा एवं कुलसचिव डॉ. अंकुर सक्सेना का सहयोग विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

उज्जैन में 5 लाख हेक्टेयर में होगी सोयाबीन की बोवनी

सरकार के पास एक लाख क्विंटल बीज, जरूरत चार लाख क्विंटल की

किसान महंगा और अप्रमाणित बीज खरीदने को मजबूर

वंदना बृजेश परमार

उज्जैन। इस वर्ष मालवा की मिट्टी में पीले सोने (सोयाबीन) की बोवनी का आंकड़ा 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। कृषि विभाग के पास एक लाख क्विंटल बीज उपलब्ध है जबकि जरूरत चार लाख क्विंटल की है। ऐसे में किसान को बाजार से महंगे दामों पर अप्रमाणित बीज को भी खरीदना पड़ रहा है। गौरतलब है कि जिले में सोयाबीन की छुटपुट बोवनी शुरू हो गई है। जिले में सोयाबीन की बोवनी की तैयारी शुरू हो गई है। किसानों को अच्छी वर्षा का इंतजार है। कृषि विभाग के अनुसार सोयाबीन की बोवनी कम से कम चार इंच की बारिश के बाद ही करना चाहिए। अभी तक 3 इंच बरसात हो चुकी है। चंदेसरा, नरवर क्षेत्र में कुछ किसान बोवनी भी कर चुके हैं। पौधे जमीन के बाहर दिखाई देने लगे हैं। इस बार किसानों को सोयाबीन का बीज काफी महंगा खरीदना पड़ रहा है। सरकार के पास 8800 रुपए क्विंटल के 1 लाख क्विंटल बीज हैं, जो कि बोवनी के रकबे के मान से अपर्याप्त है। ऐसे में किसानों को मंडियों व निजी बीज एजेंसी से 10 से 12 हजार क्विंटल में बीज खरीदना पड़ रहा है।

खूब बिक रहा मंडी नीलामी में बीज

इधर, बीज की जबरदस्त मांग के चलते कृषि मंडी में नीलामी के दौरान बीज की सोयाबीन के भाव काफी ऊंचे बताए जा रहे हैं। अलग-अलग किस्म का सोया बीज 7500 से 12000 रुपए क्विंटल तक बिक रहा है। वहीं सोया प्लांटों की लेवाली के अभाव में सोयाबीन 6000 से 6200 रुपए क्विंटल ही बिक रही है। यहां के बीज का सोयाबीन ग्वालियर, गुना लाइन के कई कारोबारी खरीद कर ले जा रहे हैं।

कुछ जगह हो गई बोवनी

चंदेसरा के किसान नंदकिशोर पटेल ने बताया कि बीते दिनों अच्छी बारिश हो जाने के बाद क्षेत्र में बोवनी कर दी गई। पौधे जमीन के बाहर भी आ गए हैं। इस बार 2069, 2034, 1025, एनआरसी 37 किस्म सोया बीज की बोवनी ज्यादा की जा रही है। इनका उत्पादन 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बताया जा रहा है।

जिले में 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बोवनी में 4 लाख क्विंटल बीज लगता है, जिसमें 1 लाख क्विंटल सरकार उपलब्ध करवा रही है। शेष बीज किसानों के पास उपलब्ध रहता है, क्योंकि किसान सोयाबीन की फसल तैयार होने पर उसी में से बीज बनाकर पुन: बो सकता है। यह प्रक्रिया 3 साल तक जारी रख सकता है। बावजूद बीज की कमी बनी हुई है। यही कारण है कि मंडी नीलामी में अप्रमाणित सोया बीज 8 से 12 हजार रुपए क्विंटल बिक रहा है।
कमलेश राठौर, कृषि अधिकारी, उज्जैन

मोदी सरकार ने 2,516 करोड़ रुपए की दी मंजूरी

कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्र ने खोला खजाना

जागत गांव हमार। भोपाल/नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण के लिए 2,516 करोड़ रुपए के खर्च की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में यह फैसला किया गया। इस कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य पैक्स की दक्षता बढ़ाने के साथ उनके संचालन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाना है। इसके तहत पैक्स को अपने व्यवसाय में विविधता लाने तथा विभिन्न गतिविधियां/सेवाएं शुरू करने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी।

किसानों को होगा फायदा

उन्होंने कहा कि पांच साल में लगभग 63,000 कार्यरत पैक्स के कंप्यूटरीकरण का प्रस्ताव है। इस परियोजना पर कुल 2,516 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें केंद्र सरकार 1,528 करोड़ का बोझ वहन करेगी। इस निर्णय से 13 करोड़ विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों को फायदा मिलेगा। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है और इस क्षेत्र में एक बड़ा सुधार है।

पैक्स को हार्डवेयर संबंधी सहायता दी जायेगी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस परियोजना में साइबर सुरक्षा और डेटा भंडारण के साथ क्लाउड-आधारित सामान्य सॉफ्टवेयर के विकास समेत पैक्स को हार्डवेयर संबंधी सहायता प्रदान करना शामिल है। इस संबंध में जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि पैक्स देश में अल्पकालिक सहकारी ऋण (एसटीसीसी) की तीसरे स्तर की व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर अपनी भूमिका निभाता है।

13 करोड़ किसान पैक्स के सदस्य

इसमें लगभग 13 करोड़ किसान इसके सदस्य होते हैं और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। देश में सभी संस्थाओं की तरफ से दिए गए केसीसी ऋणों में पैक्स का हिस्सा 41 प्रतिशत (3.01 करोड़ किसान) है। पैक्स के माध्यम से इन केसीसी ऋणों में से 95 प्रतिशत (2.95 करोड़ किसान) छोटे व सीमांत किसानों को दिए गए हैं।

पैक्स की पहुंच होगी बेहतर

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सभी पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने और उनके रोजमर्रा के कार्य-व्यवहार के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक साझा मंच पर लाने तथा एक सामान्य लेखा प्रणाली (सीएएस) के तहत रखने का प्रस्ताव रखा गया है। यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण को बेहतर बनाने के अलावा बैंकिंग गतिविधियों के साथ-साथ गैर-बैंकिंग गतिविधियों के केंद्र के रूप में पैक्स की पहुंच को बेहतर बनाने में मदद करेगी।

किसानों और पर्यावरण को लाभ पहुंचा रहे अगली पीढ़ी के उर्वरक

नैनो यूरिया और डीएपी का 20 साल के लिए इफको को मिला पेटेंट

जागत गांव हमार। भोपाल/नई दिल्ली

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोपरेटिव लिमिटेड (इफको) ने अपने नैनो टैक्नोलॉजी आधारित उर्वरक नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के लिए 20 साल के लिए पेटेंट हासिल किया। इफको के एमडी यूएस अवस्थी ने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी। यूरिया और डी-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) देश में बड़े पैमाने पर खपत वाले उर्वरक हैं। इफको ने अपने नैनो उत्पादों के लिए भारत सरकार से 20 साल की अवधि के लिए पेटेंट प्राप्त किया है। इफको के प्रबंध निदेशक यूएस अवस्थी ने कहा कि इफको के नैनो यूरिया और नैनो डीएपी अगली पीढ़ी के उर्वरक किसानों और पर्यावरण को लाभ पहुंचा रहे हैं। ये उत्पाद मिट्टी, वायु और जल प्रदूषण को कम करने में सहायक होंगे।

विकसित करने की दिशा में जुटा

दुनिया में भारत की यह शुरुआत अपनी तरह की पहली है। इफको यहीं नहीं रुका है, वह वर्तमान में नैनो जिंक और नैनो कॉपर भी विकसित करने की दिशा में जुटा है। नैनो डीएपी भी नैनो यूरिया की तरह से 500 एमएल की बोतल में होगी। यानी किसानों को 18 सौ रुपए की 50 किलो की बोरी की जगह, बहुत कम डीएपी में काम हो जाएगा। इसकी कीमतों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, लेकिन आकलन के मुताबिक यह छह सौ रुपए प्रति बोतल हो सकती है।

मिट्टी को स्वस्थ भी रखते हैं ये उर्बरक

अवस्थी ने कहा कि गुणवत्ता वाली फसलों की मात्रा का उत्पादन करने के लिए, इन नए उत्पादों की कम मात्रा की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ ये मिट्टी को स्वस्थ भी रखते हैं। यह मिट्टी को रसायनों के अत्यधिक उपयोग से बचाने का एक प्रयास है, जो इफको की दीर्घकालिक सोच और उसकी प्रतिबद्धता है।

कृषि लागत में कमी लाकर मजबूत करेगा पेटेंट

इफको नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का पेटेंट भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि लागत में कमी लाकर मजबूत करेगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने और उनकी प्रेरणा के मुताबिक किसानों की आय को दोगुनी करेगा। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में पूर्णतया स्वदेशी नैनो खाद पर्यावरण मित्र और फसलों के अनुपात में इस्तेमाल का गुण होने के कारण स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अनुकूल होगी।

जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगी

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोपरेटिव लिमिटेड, इफको को यह सफलता उसके गुजरात के कलोल स्थित नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर-एनबीआरसी के वैज्ञानिकों ने दिलाई है। यह नैनो खाद जल्द ही बाजार में उपलब्ध हो इसके लिए युद्धस्तर पर काम शुरू हो गया है। इससे पहले, पिछले साल जुलाई से ही इफको नैनो यूरिया विकसित कर किसानों को दे रहा है।

उद्यानिकी विभाग में कई योजनाओं के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित

जागत गांव हमार। इंदौर

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा इन्दौर जिले के लिए पुष्प क्षेत्र विस्तार, सब्जी क्षेत्र विस्तार, मसाला क्षेत्र विस्तार, ड्रेगन फ्रूट व अंजीर क्षेत्र विस्तार,स्प्रे पम्प 16 लीटर, जैविक खेती वर्मी बेड, तालाब/कुआं सृजन, मधुमक्खी पालन सेट, पाली हाउस, शेडनेट हाउस, छोटा ट्रैक्टर, छोटे ट्रैक्टर के निंदाई, जुताई, खुदाई आदि उपकरण , मल्चिंग बिछाने की मशीन, पैक हाउस, समेकित भंडार गृह, कम लागत के प्याज भंडार गृह 25 मैट्रिक टन , स्थिर चलित विक्रय/ शीत चलित ठेला आदि योजनाओं के लिए किसानों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।

ओपी ठाकुर, प्रभारी वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, देपालपुर ने बताया कि उक्त योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। किसान एमपीएफएसटीएस उद्यानिकी विभाग के पार्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कर योजना में आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अभी जिलेवार लक्ष्य तय नहीं हुए हैं, लेकिन पंजीयन किए जा रहे हैं। पंजीयन की अंतिम तिथि 5 जुलाई निर्धारित की गई है।

अधिक जानकारी के लिए किसान ओपी ठाकुर, प्रभारी वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, देपालपुर,मोबाईल 7354019744 , रोहित अलावे, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी ,केंद्र-देपालपुर/बेटमा मोबाईल नंबर 7000516376 और चन्दरसिंह मंडलोई , ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी,केंद्र-गौतमपुरा मोबाईल 9754601954 से संपर्क करें। जहां किसानों को पूरी जानकारी मुहैया कराई जाएगी।

एआईसीएल और रिलायंस को दी मप्र में फसल बीमा की जिम्मेदारी

जागत गांव हमार। भोपाल

भोपाल। मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत चयनित दो कंपनियों को क्लस्टर के मुताबिक जिलों का आवंटन कर दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक 11 क्लस्टरों में से 2 क्लस्टर के चार जिले भोपाल, सीहोर, इंदौर एवं देवास रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को तथा शेष 9 क्लस्टरों के 48 जिले एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि. (एआईसीएल) को आवंटित किए गए है। इन जिलों में उक्त कंपनियां फसलों का बीमा करेंगी।

एआईसीएल को आवंटित जिले

उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा, रायसेन, विदिशा, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, दतिया, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, मुरैना, श्योपुर कलां, भिंड, राजगढ़, जबलपुर, कटनी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, डिण्डोरी, सिवनी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, नर्मदापुरम (होशंगाबाद), हरदा, बैतूल, रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, सागर दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना एवं निवाड़ी। गौरतलब है कि वर्ष 2022-23 में फसल हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोग के आधार पर न होकर रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाएगा। खरीफ की अधिसूचित फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।

नील हरित शैवाल और उसकी उपयोगिता

फसलों के उचित बाढ़ एवं अधिक उपज के लिए पोषक तत्वों खासकर नेत्रजन, स्फूर एवं पोटाश की आवश्यकता होती है। इन तीनों पोषक तत्वों में नेत्रजन की जरूरत ज्यादा होती है। वैसे तो नेत्रजन मिट्टी में भी पाया जाता है परन्तु लगातार खेती करने से इनकी मात्रा मिट्टी से कम हो जाती है। अत: इसे उर्वरक के रूप में पौधों को उपलब्ध कराया जाता है। कुछ जीवाणु भी हैं, जो वायुमंडलीय नेत्रजन को पौधों उपलब्ध कराते हैं, जैसे -राइजोबियम दलहनी फसलों में, ऐजोटोवैक्टर, गेहूं, सब्जीयों एवं कपास इत्यादि में तथा नील हरित शैवाल जिसे काई भी कहते हैं, धान की फसल में नत्रजन उपलब्ध कराते हैं।

ये जीवाणु उर्वरक के रूप में व्यवहार में लाए जाते हैं। खड़ी फसल के आलावा बाद वाली फसल को भी नत्रजन उपलब्ध कराते हैं। नील हरित शैवाल खाद के द्वारा अधिक उपज प्राप्त करने के लिए धान की रोपनी समाप्त होने के एक सप्ताह बाद खेत में 5-7 सेमी पानी भरें। यदि पानी नहीं हो तो उसके बाद खेत में 10 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से नील हरित खाद का छिड़काव बराबर रूप से कर दें। खेत में शैवाल डालने के बाद कम से कम 10 दिनों तक पानी भरा रहना चाहिए। इस तरह से एक ही खेत में कई सालों तक लगातार प्रयोग करते रहने से ये खाद आने वाले कई एक सालों तक डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस प्रकार शैवाल खाद का पूरा लाभ फसलों को मिलता है जिससे उपज में वृद्धि होती है। नील हरित शैवाल खाद के प्रयोग से लगभग 30 किग्रा नत्रजन प्रति हेक्टेयर की प्राप्ति होती है, जो लगभग 65 किग्रा यूरिया के बराबर है। इसके प्रयोग से उपज में 0-15 प्रतिशत की वृद्धि अलग से होती है। यह स्वयं जैविक प्रवृति के होने के कारण अनेक उपयोगी अ ल, विटामिन एवं पादप हारमोन भी भूमि में छोड़ते हैं, जो कि धान के पौधों के लिए लाभदायक है। इन सभी के अलावा यह ऊसर भूमि सुधारने में भी मदद करता है। नील हरित शैवाल खाद को किसान भाई कम खर्च में अपने घरों के आस पास बेकार पड़ी भूमि में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां सूर्य का प्रकाश और शुद्ध हवा प्रर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। इसे बनाने के लिए गैल्वानाइजड (जंगरोधी लोहे की चादर) लोहे की शीट से2 मी. लम्बा, 1 मी. चौड़ा तथा 15 सेमी ऊंचा एक ट्रे बना लें। इस प्रकार का ट्रे इंट एवं सिमेंट के द्वारा भी बना सकते हैं। या फिर इसी साइज का गड्ढा खोद कर उसमें नीचे पोलीथीन शीट बीछा कर पानी डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्रे में सबसे पहले 10 किग्रा दोमट मिट्टी में 200 ग्राम सुपरफास्फेट खाद एवं 2 ग्राम चूना भी मिलाएं। इस ट्रे में इतना पानी भरें कि 5-10 सेमी की ऊचाई तक हो जाए। उसे कुछ घंटों तक छोड़ दें जिससे मिट्टी अच्छी तरह बैठ जाएं। इसके बाद पानी की सतह पर एक मुट्टी नील हरित शैवाल का प्रारंभिक कल्चर छिड़क दें। 7-8 दिनों के बाद गहरे हरे रंग की काई की परत दिखाई पड़ने लगती है। अब पानी को सुखने के लिए छोड़ दें और जब पानी सुख जाय तो काई या शैवाल को आधा सेमी की गहराई तक खुरच कर थैले में भर लें। फिर ट्रे में पानी डालकर इस क्रिया को दो तीन बार दुहराएं। एक बार भरे ट्रे से लगभग 1.5 से 2 किग्रा शैवाल खाद की प्राप्ति होगी। यह कार्यक्रम सालों भर चला कर शैवाल खाद बनाया जा सकता है। ट्रे या गड्ढे को ऐसे जगह पर रखे या बनाएं जहां पूरी मात्रा में धूप एवं हवा आती हो, क्योंकि धूप से ही इसमें गुणन विधि या फैलाव ज्यादा एवं जल्दी होता है। ट्रे में हमेशा पानी भरा रहे इसका भी ध्यान रखना चाहिए यदि मिट्टी अम्लीय हो तो चूना अवश्य डालें। विभिन्न परियोजनाओं के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में किए गए मिट्टी यानि मृदा विश्लेषण से कम से कम 6 पोषक तत्वों- नाइट्रोजन, फास्फोरस), पोटाश), जिंक और बोरॉन की व्यापक कमी प्रदर्शित हुई। उत्तर-पश्चिमी भारत के चावल-गेहूं उगाए जाने वाले क्षेत्रों में किए गए कुछ नैदानिक सर्वे से पता लगा कि किसान उपज स्तर को बनाए रखने के लिए, जिन्हें पहले कम उर्वरक उपयोग के जरिए भी हासिल कर लिया जाता था, अक्सर उचित दरों से ज्यादा नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन यह एक फसल को लगने वाला महत्वपूर्ण पौष्टिक तत्व है। नाइट्रोजन प्रकृति में विविध रूपों में पाया जाता है। जैसे की वायु मंडल में (नाइट्रोजन) वायु रूप में सबसे ज्यादा मात्रा में लगभग 78 फीसदी मौजूद है। लेकिन इस वायु रूप नाइट्रोजन का इस्तेमाल वनस्पति को नहीं मिल पाता। वनस्पति में आरएन ए, डीएन ए, अमीनो एसिड और प्रोटीन निर्माण में नाइट्रोजन अहम भूमिका निभाता है। इसलिए नाइट्रोजन की कमी से फसल की उपज में भारी कमी हो सकती है। अगर आप नाइट्रोजन चक्र समझ जाएंगे तो, रासायनिक खादों का उपयोग कम करके प्राकृतिक तरीके से मिट्टी में नाइट्रोजन का प्रमाण बढ़ा सकते है। इस वायु मंडल में उपलब्ध नाइट्रोजन वायु को सजीव के लिए उपलब्ध कराना और फिर से उसे नाइट्रोजन वायु के रूप में परिवर्तित कराना, इसे नाइट्रोजन चक्र कहेंगे। यह चक्र कई जैविक और भौतिक प्रक्रिया पर निर्भर है। हम जानते हैं की कुछ बातों से वायुमंडल में उपलब्ध नाइट्रोजन का बिजली से प्रक्रिया होकर, बारिश के पानी के द्वारा पौधों को उपलब्ध होती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादातर नाइट्रोजन कुछ खास जीवाणुओं से राइजोबियम पौधों को उपलब्ध होता है। इसे नाइट्रोजन स्थरीकरण कहते है। यह जीवाणु नाइट्रोजन को अमोनियम आयन के रूप में पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। इसे वनस्पति अमीनो एसिड के रूप में उपयोग करते हैं। इस अवस्था में नाइट्रोजन जैविक रूप में वनस्पति और प्राणी जगत में पाया जाता है। वनस्पति या प्राणी अपनी बेस्ट प्रोडक्ट में या जब वे अपनी जीवन यात्रा खत्म करते हैं, तो उस समय वे जैविक रूप में मौजूद नाइट्रोजन का कुछ बैक्टरिया और फंगस के माध्यम से पृथक्करण होकर अमोनिया में परिवर्तित होता है। इसे अमोनिफिकेशन कहते है। अमोनिफिकेशन से मिलने वाला अमोनिया और फिर से कुछ बैक्टरिया से परिवर्तित होकर नाइट्राट और बाद में नाइट्रेट तैयार होता है। इसे नइट्रिफिकेशन कहते है। इसके पश्चात कुछ जीवाणु से (स्यूडोमोनास) डिनात्रीफिकेशन होकर, नाइट्रोजन वायु तैयार होकर वातावरण में मिल जाता है और इस तरह से नाइट्रोजन चक्र पूरा होता है। इन सब बातों से हम ये कह सकते हैं कि, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु से बीज उपचार और अधिकतम जैविक खादों का इस्तेमाल, नाइट्रोजन चक्र की तंदुरस्ती बरकरार रखता है।

लेखक: डॉ. डीके रैदास, सहायक प्राध्यापक, डॉ. मनोज कुमार तरवरिया, शस्य विज्ञान, डॉ. नेहा सिंह किरार, शस्य विज्ञान, आरएके कृषि महाविद्यालय सीहोर, डॉ. ओमप्रकाश धुर्वे, सहायक प्राध्यापक, कृषि महाविद्यालय गंजबासौदा, विदिशा

करौंदा का पौधा फेंसिग और फल दोंनो के लिए उपयोगी

करौंदा (कैरिसा कैरन्डास) एपोसाइनेसी कुल का एक झाड़ीनुमा, बहुवर्षीय एवं सदाबहार पौधा है। करौंदा की झाड़ी में अत्यंत नुकीले कांटे पाए जाते हैं। यह पौधा भारत में राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। घनी कांटेदार झाड़ी होने के कारण करौंदा प्रायः जीवित बागड़ के रूप में बाग-बगीचों तथा खेतों में लगाया जाता है, जिससे जानवरों से फसल, पेड़-पौधों की सुरक्षा के साथ इससे अतिरिक्त आय प्राप्त होती है।

झाड़ियों की ऊंचाई 3-4 मीटर तक हो जाती है। इसकी पत्तियां छोटी व अंडाकार आकार की होती हैं। नई पत्तियों पर हल्की लालिमा पाई जाती है। फूल सफेद अथवा गुलाबी रंग के, सुगंधित तथा गुच्छों में आते हैं। इसको मुख्यत: वर्षा आधारित क्षेत्रों में उगाया जाता है। एक बार करौंदा के पौधे लगाने के बाद, कम देखभाल एवं प्रबंधन में भी अच्छी उपज ली जा सकती है। पहाड़ी क्षेत्रो में जल संरक्षण में सहायक है। किसान अपने खेत में करौंदा की जीवित बागड़ (फेसिंग) से अपनी फसलों को जानवरों से सुरक्षा कर सकते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए करौंदा की झाड़ी बहुत ही उपयोगी एवं लाभकारी रहेगी। करौंदे के फल में पौष्टिक तत्वों का खजाना विद्यमान है। इसमें पेक्टिन, कार्बोहाइड्रेट व विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके शुष्क फलों से 364 कैलोरी ऊर्जा, 23 प्रतिशत प्रोटीन, 2.8 प्रतिशत खनिज लवण, 9.6 प्रतिशत वसा और 67 प्रतिशत कार्बोहाईड्रेट प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। करौंदा के फल में विटामिन काम्प्लेक्स एव फोलिक एसिड का एक उत्तम स्रोत है। लौह की प्रचुरता होने के कारण एनीमिया रोग में उपचार के लिए करौदा एक अत्यन्त लाभकारी फल है। पहले महिलाये करौदा को खाती थी तो लोहें की कमी नही होती थी लेकिन वर्तमान में लोहें के लिए आयरन की गोलियां खाना पड़ता है। कांटेयुक्त होने के कारण करौंदा की झाड़ियों गर्म जलवायु तथा सूखे के प्रति सहनशील है। इसलिए करौंदा सम्पूर्ण भारत के उष्ण, समशीतोष्ण, शुष्क एवं अर्द्धशुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में सफलता पूर्वक लगाया जाता है। करौंदा की खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, परन्तु उपयुक्त जल निकास एव 6-8. पी एच मान वाली बलुई दोमट भूमि करौंदे के लिए सर्वोत्तम होती है। करौंदे की उन्नत किस्मे कैरिसा इब्लिसा, मनोहर, पंत स्वर्ण, सीआईएसएच करौंदा-2 को माना गया है। करौंदे के पौधों को प्रारंभिक वर्षों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। पुष्पन एवं फलन के समय ही भूमि में नमी की आवश्यकता रहती है। कीट एवं व्याधि प्रबंध का प्रकोप कम देखा गया है। करौंदा के पौधों की रोपाई जुलाई-अगस्त तथा सिंचित क्षेत्र फरवरी-मार्च माह में की जा सकती है। करौंदा के पौधों बागड़ के रूप में लगाने के लिए कम दूरी रखना चाहिए। करौंदा लगाने के लिए वर्गाकार अथवा आयताकार विधि 3 × 3 या 4×4 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। रोपण से लगभग एक माह पहले 30-40 सेमी आकार के गड्ढे खोद कर उनमें 25-30 किलो सड़ी गोबर की खाद मिट्टी में मिलाकर भर देना चाहिए। करौंदे की उपज जलवायु, पौधों की वृद्धि और प्रबंधन पर निर्भर करती है। करौंदा के एक झाड़ी से लगभग 15-25 किलो, फल प्राप्त हो जाते है। तुड़ाई उपरांत फलों को छायादार स्थान पर रखना चाहिए। कमरे के सामान्य तापमान पर करौंदा के फलों को एक सप्ताह तक रखा जा सकता है। इसके परिपक्व फल जल्दी खराब होने लगते हैं।

लेखक- डॉ. सुनील कुमार जाटव, डॉ. बीएस किरार, डॉ.एसके सिंह, डॉ.आरके प्रजापति, डॉ.यूएस धाकड़, जयपाल छिगाराह, वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ़

गाय के घी के स्वास्थ्य लाभ

प्राचीन काल से भारत में गाय के घी का सेवन बहुत प्रचलित है। आयुर्वेद में भी इसके कई लाभ बताए गए हैं। गाय का घी भैंस के घी, मक्खन आदि से अधिक लाभप्रद है। गाय के घी में अनेक लाभकारी विटामिन्स जैस विटामिन ए,सी, डी, के और ई विटामिन जहां एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में त्वचा एवं बालो को स्वस्थ्य रखता है। वही विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक है। मोतियाबिंद,रतौंधी जैसे नेत्र रोगों में गाय का घी उपयोगी सिद्ध हुआ है। जोड़ों से संबंधित रोगों जैसे गठिया वात आदि में भी यह लाभदायी है, क्योंकि जोड़ों में होने वाली सूजन को कम करने में यह मदद करता है। साथ ही घी के इस्तेमाल से हड्डियां भी मजबूत होती है। जले हुए घाव पर भी गाय के घी के इस्तेमाल से दर्द एवं जलन से राहत मिलती है, क्योंकि गाय के घी में ब्यूटेरेट की मात्रा अधिक होती है। कोरोना काल में भी इसका उपयोग नासिका में करने से श्वांस संबंधी रोगों/समस्याओं के लिए लाभदायक पाया गया। गाय का घी खाने का स्वाद बढ़ने के साथ साथ भोजन के पाचन में भी मदद करता है तथा पेट के छालों एवं कैंसर जैसी समस्याओ को भी कम करता है। संतुलित मात्रा में गाय के घी का सेवन मोटापे को भी कम करता है, क्योंकि इसमें पीयूएफए (पोली अंसेचुरेटेड फैटी एसिड) की मात्रा अधिक होती है, जो कोलेस्टेरोल के स्तर को हमारे रक्त में कम करके हृदय रोगों की संभावना को भी कम करता है। गाय के घी के इस्तेमाल से रोगप्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। आयुर्वेद में गाय के घी को मेध/मेधा रसायन कहा गया है, क्योंकि यह मष्तिष्क में तंत्रिकाओं का विकास कर याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है। हार्मोन के नियंत्रण में भी इसकी भूमिका देखी गई है। जैसे की थायरॉइड, एवं मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं में इसके लाभकारी परिणाम देखे गए हैं। नाभि में गाय के घी के लेप से त्वचा में चमक, चर्म रोगों से छुटकारा, बाल झड़ने की समस्या, जोड़ों के दर्द एवं कब्ज की शिकायत में आराम देखा गया है। मिर्गी के रोगी में भी गाय के घी के लाभकारी परिणाम देखे गए हैं। बेहतर परिणाम के लिए घी देशी एवं स्वस्थ्य गाय से प्राप्त होना चाहिए। नियमित व्यायाम के साथ संतुलित मात्रा इसके उपयोग से हृदय रोग आदि में भी इसके गुणकारी प्रभाव देखे गए हैं। वर्तमान समय में लोगो ने घी को छोड़ कर रिफाइंड तेल ऑलिव आयल आदि का इस्तेमाल बढ़ा दिया है, क्योंकि लोगों में गाय के घी के लाभ के प्रति अनभिग्यता है। लोगों के बीच गाय के घी विभिन्न स्वास्थ्य वर्धक गुणों की जानकारी इसकी लोकप्रियता तथा उपयोग को बढ़ा सकती है।

लेखक-डॉ. शिवानी मुड़ोतिया, डॉ. भावना गुप्ता, डॉ. रणविजय सिंह, डॉ. रुचि सिंह, डॉ. बृजमोहन सिंह धाकड़, डॉ. रेनू चाहर, पशु जान स्वास्थ्य एवं महामारी विभाग, पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय जबलपुर

किसान इसकी खेती से कमाएं बंपर मुनाफा,500 से 5000 रुपए किलो तक बिकती है

काली हल्दी की खेती किसानों को कर सकती है मालामाल

जागत गांव हमार। भोपाल

पारंपरिक फसलों में लगातार कम होते फायदे की वजह से किसानों ने अब पारंपरिक फसलों की खेती की तरफ रुख करना शुरू किया है। इसी कड़ी में किसानों के बीच पिछले कुछ सालों में हल्दी की खेती का चलन बढ़ा है। हालांकि, अभी किसानों को सबसे ज्यादा पीली हल्दी की खेती करते हुए देखा जा सकता है। यह हम आपको काली हल्दी की खेती से किसान किस तरह से बंपर मुनाफा कमा सकते हैं, इस बारे में बता रहे हैं। काली हल्दी के बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसी वजह से मार्केट में इसकी कीमत भी ज्यादा है। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट बनाने में भी काली हल्दी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा डॉक्टर्स भी निमोनिया, खांसी, बुखार, अस्थमा जैसी दिक्कतों में इसके सेवन की सलाह देते हैं। इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारियों में उपयोग होने वाली दवाओं को बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।

काली हल्दी की खेती

काली हल्दी की खेती के लिए जून का अंतिम और जुलाई का शुरुआती हफ्तों में की जाती है। इसके लिए भुरभुरी दोमट मिट्टी काफी उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा ऐसे खेत का चुनाव करें जहां जल निकासी की व्यवस्था बेहतर हो। खेत में बारिश का पानी रुकने से फसल बर्बाद हो सकती है। एक हेक्टेयर में काली हल्दी के करीब 2 क्विंटल बीज लग जाते हैं। काली हल्दी को अधिक सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसके लागत में भी ज्यादा खर्च नहीं आता है। औषधीय गुण होने की वजह से फसल में कीट भी नहीं लगता है।

मिलती है इतनी कीमत

एक एकड़ में कच्ची हल्दी करीब 50-60 क्विंटल यानी सूखी हल्दी का करीब 12-15 क्विंटल तक का उत्पादन हो जाता है। मार्केट में काली हल्दी 500 रुपए से 4 हजार रुपए किलो तक बिकती हुई पाई जाती है। इसके अलावा कई ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर इस हल्दी की कीमत 5 हजार रुपए तक दिखाई देते हैं। ऐसे में काली हल्दी की खेती कर किसान को पास बंपर मुनाफा कमाने का बेहतरीन मौका होता है।

खुद किसान अपने मोबाइल से दर्ज करा सकते है अपने खेत में बोई जाने वाली फसल की जानकारी

ऑनलाइन होगी फसल गिरदावरी, किसानों को नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर

जागत गांव हमार। श्योपुर

खरीफ और रबी सीजन के दौरान खेत में बोई जाने वाली फसलों की जानकारी भू-अभिलेख के रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए अब किसानों को पटवारी और राजस्व अधिकारियों के यहां चक्कर काटने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। क्योंकि अब सरकार के द्वारा फसल की जानकारी सारा एप पर जियो फेंस तकनीक का इस्तेमाल कर ऑनलाइन गिरदावरी की रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

खास बात यह है कि ऑनलाइन दर्ज होने वाली फसल जानकारी की रिपोर्ट किसान स्वयं अपने मोबाइल पर एमपी किसान एप के जरिए देख सकते है और जानकारी गलत होने पर उसमें सुधार अपने मोबाइल के जरिए ही करवा सकते है। यहां बता दें कि पहले साल में दो बार फसल गिरदावरी प्रक्रिया होती थी, लेकिन अब फसल गिरदावरी की प्रक्रिया साल में तीन बार होती है। गिरदावरी के दौरान खेत की जानकारी, कितने रकबे में कितनी और कौन सी फसल बोवनी की है इसकी जानकारी प्राप्त कर भू-अभिलेखों दर्ज होती है। आंकड़ों के आधार जिले का रकबा पता चलता है। प्राकृतिक आपदा के समय प्रभावित किसान को मुआवजा के समय यह रिपोर्ट उपयोगी हो जाती है। अब तक गिरदावरी पटवारियों द्वारा कागजों में दर्ज की जाती थी। इसमें कई बार तो एक जगह बैठकर ही सभी जानकारी दर्ज कर ली जाती थी। कई बार किसान को भी जानकारी नहीं होती थी, लेकिन अब जियो फेंस तकनीक के जरिए फसलों की गिरदावरी ऑनलाइन दर्ज हो जाएगी।

हां, अब ई-गिरदावरी शुरू हो गई है। एमपी किसान एप के जरिए किसान स्वयं ही अपने खेत की फसल की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं।
राकेश वर्मा, प्रभारी अधीक्षक, भू अभिलेख,श्योपुर

जियो फेंस तकनीक

कृषि क्षेत्र में सरकार की ओर से निरंतर नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसी ही नई तकनीक का प्रयोग अब मध्यप्रदेश सरकार ने किया है। जिसके तहत किसानों की फसलों की सही गिरदावरी सीधे एप पर अपलोड की जाएगी, जिसे आमजन द्वारा पोर्टल पर देखा जा सकता है। बताया गया है कि गुणवत्तापूर्ण फसल गिरदावरी कार्य सुनिश्चित करने के लिए सारा एप में जियो फेंस तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

ये होगा फायदा

पटवारी घर बैठकर फसल का रकबा दर्ज नहीं कर सकेंगे। फसल बीमा, प्राकृतिक आपदा, बैंक ऋण, योजनाओं के लाभ के लिए पटवारियों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे।

किसान मोबाइल पर भी देख सकते है फसल गिरदावरी की रिपोर्ट

किसान अपने खेत की ऑनलाइन गिरदावरी रिपोर्ट अपने मोबाइल भी देख सकते हैं। इसके लिए किसानों को अपने मोबाइल पर एमपी किसान एप डाउनलोड करना पड़ेगा। इस एप के जरिए किसानों को अपने खेत की गिरदावरी रिपोर्ट ऑनलाइन दिख जाएगी। रिपोर्ट गलत होने पर किसान अपने मोबाइल से खेत पर फसल की फोटो एप के जरिए भेजकर उसमें न सिर्फ सुधार भी करवा सकता है,बल्कि खुद ही गिरदावरी रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। यह कार्य 15 अगस्त तक होगा।

गाय के गोबर से बनाया जाता है कागज

गौ-पालकों पर होगी गोबरधन की वर्षा

जागत गांव हमार। भोपाल/नई दिल्ली

गांवों में गाय-भैंस के गोबर इस्तेमाल अधिकतर पशुपालक उपले बनाने के लिए करते नजर आते हैं या तो फिर उसे बेकार समझ कर फेंक देते हैं। हालांकि, आज के दौर में गोबर का उपयोग उपले बनाने से लेकर खेतों के लिए खाद बनाने के तौर पर किया जा रहा है। इसके अलावा गोबर से कई अन्य तरह के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, उनकी बाजार में बेहद डिमांड है। किसान गोबर का उपयोग बायोगैस, अगरबत्ती, दीए, कागज, सीएनजी प्लांट, गमला जैसे कई तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। यहां हम किसानों और पशपालकों को गोबर के इन उपयोगों के बारे में बताने जा रहे हैं। गाय-भैंस के गोबर का इस्तेमाल करके पेपर तैयार किया जा सकता है। भारत सरकार भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पशुपालकों से गोबर खरीद उन्हें आर्थिक तौर पर सहायता प्रदान किया जाएगा।

बायोगैस प्लांट

गौपालक गोबर से बनी बायोगैस प्लांट लगवाकर अच्छा लाभ कमा सकते है। प्लांट लगाने के लिए आप सरकार से भी आर्थिक मदद प्राप्त कर सकते हैं।

अगरबत्ती में उपयोग

अगरबत्ती बनाने में गोबर का उपयोग किया जाता है। कई कंपनियां पशुपालकों से ठीक-ठाक दामों पर गोबर खरीदती हैं। उसका उपयोग सुगंठित अगरबत्तियां बनाने में करती हैं।

खाद में उपयोग

आज कल सरकार भी किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसकी खेती में खाद के तौर पर गोबर का इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके उपयोग से किसान जीवामृत से लेकर केंचुआ खाद बना कर उसका उपयोग कर अपने फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं।

गोबर से बनाएं मूर्ति और गमले

गोबर से इन दिनों मूर्तियां बनाने का चलन भी बड़ी तेज बढ़ा है। मिट्टी के मुकाबले गोबर से मूर्तियां बनाने में लागत कम आती है और आप मुनाफा भी ज्यादा कमा सकते हैं। गोबर से मूर्तियां बनाने के लिए मेक इन इंडिया, क्लीन इंडिया व ग्रीन इंडिया के तहत अभियान भी चलाया जा रहा है। महिलाएं इस तरह के काम में बढ़-चढ़कर भाग ले रही हैं। इसके अलावा गोबर का उपयोग गमले बनाने में भी किया जाता है।

मंडलेश्वर के किसान ने ट्रैक्टर से बनाई बिजली

खरगौन। निमाड़ के किसान इन दिनों बारिश की लम्बी खेंच से यूं ही परेशान हैं, उस पर गांवों में 10 घंटे बिजली की आपूर्ति होने से किसानों का सिंचाई का समय गड़बड़ गया है। इन हालातों को देखते हुए खरगोन जिले के ग्राम पथराड़ के किसान गणेश पाटीदार ने बिजली संकट से निजात पाने के लिए ट्रैक्टर से बिजली उत्पादन करने की क्षेत्र में नई पहल की है, जो चर्चा का विषय बनी हुई है। किसान गणेश पाटीदार ने बताया कि गांव में बिजली सुबह 4 से 8 और दोपहर को 3 से रात को 9 बजे तक दी जाती है। इससे सिंचाई कार्य का समय गड़बड़ा जाता है, इसलिए ट्रैक्टर से बिजली उत्पादन का प्रयोग किया गया है। इसके लिए घर में रखे पुराने आर्मेचर का उपयोग किया गया है, जिससे 440 वाल्ट बिजली पैदा होती है। इस बिजली से मोटर चलाकर खेत में 15 एकड़ में लगी खरीफ की मक्का/कपास की फसल में सिंचाई की जा रही है। ट्रैक्टर से बिजली बनाने में ढाई लीटर /घंटा डीजल की खपत होती है। वैसे ट्रैक्टर को 10 घंटे निरंतर चलाकर बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन 6 घंटे बाद बिजली आ जाने पर इसे बंद कर दिया जाता है।

कृषि वैज्ञानिक ई. मनोज कुमार राय ने किसानों को दी जानकारी

ऑटोमेटिक ड्रिप इरिगेशन और फर्टिगेशन सिस्टम से करें सिंचाई और उर्वरक प्रंबधन

जागत गांव हमार। भोपाल

वैज्ञानिकों ने कम पानी में भी अधिक रकबे में सिंचाई के लिए ऑटो ड्रिप इरिगेशन फर्टीगेशन तकनीक ईजाद की हुई है। पानी के साथ ही फर्टिलाइजर का सही इस्तेमाल कर कम लागत में अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। ऑटोमेटिक ड्रिप इरिगेशन और फर्टिगेशन सिस्टम क्या है? इसको लेकर बिहार स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र किशनगंज के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक और प्रमुख ई. मनोज कुमार राय ने इस तकनीक को लेकर विस्तार से **'जागत गांव हमार'** से खास बातचीत की। कम दबाव और नियंत्रण के साथ सीधे फसलों की जड़ में उनकी आवश्यकतानुसार पानी देना ही ड्रिप इरिगेशन कहलाता है। ड्रिप सिंचाई में पानी के साथ ही उर्वरकों को भी पौधों तक पहुंचना फर्टिगेशन कहलाता है।

ऑटोमेटिक ड्रिप इरिगेशन और फर्टिगेशन सिस्टम

कृषि वैज्ञानिक ई. मनोज कुमार राय ने कहा कि इस तकनीक की मदद से पानी, ऊर्जा और मजदूरी की बचत होती है। किसान ऑटोमेटिक तरीके से संचालित ऑटोमेटिक ड्रिप इरिगेशन और फर्टिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर अपनी खेती से भरपूर पैदावार ले सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि ड्रिप सिंचाई में जैसे ड्रिपर्स द्वारा ड्रिप सिंचाई की जाती है। वैसे ही फर्टिगेशन तकनीक में सिंचाई के पानी में उर्वरकों को मिलाया जाता है। फिर इंटरसेप्टर की मदद से ड्रिपर्स द्वारा उर्वरकों को सीधे पौधों तक पहुंचाया जाता है।

सटीक उर्वरक प्रबंधन की बेहतर तकनीक

कृषि वैज्ञानिक ई. मनोज राय ने बताया कि इसी तरह फसलों के लिए फर्टिगेशन यूनिट लगे होते हैं। ऑटोमेटिक तरीके से फसलों को उर्वरक दिया जाता है यानि फर्टिगेशन किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन ,फास्फोरस, पोटाश और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के घोल के लिए टैंक होते हैं जो फर्टिलाइजर डोजिंग पाइप से जुड़े होते हैं। फर्टिगेशन के लिए डोजिंग पाइप वॉल्व लगे होते हैं, जो कंट्रोलर से कंटोल किया जाते हैं। इससे फसलों की जरूरत के अनुसार फर्टिलाइजर दिया जाता है। इसमें भी कंटोलर में प्रोगाम सेट में कर दिया जाता है कि किस फसल को कितना फर्टिलाइजर किस समय दिया जाना है। कंट्रोलर से सारी जानकरी मिलती रहती है। कंट्रोलर यह भी जानकारी देता है कि कब कितना फर्टिलाइजर दिया है और किस फसल को दिया गया है। इस सिस्टम की इन्हीं खूबियों के कारण आप अपने अलग-अलग बगीचे या खेतों में लगी अलग-अलग फसलों को उनकी जरूरत के मुताबिक कम या ज्यादा पानी की सप्लाई दे सकते हैं। इस सिस्टम के जरिए नियमित समय पर संतुलित मात्रा में पानी पौधों तक पहुंच जाएगा। इसके लिए आपको न मजदूर लगाने की जरूरत होगी, न खेत का निरीक्षण करने की और कम पानी में ही पूरी सिंचाई हो जाएगी।

सही समय पर मिलता फसलों को पानी और उर्वरक

आमतौर पर फर्टिगेशन में केवल घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दानेदार उर्वरक से भी फर्टिगेशन किया जा सकता है। आज के समय में घुलनशील उर्वरक बाजार में उपलब्ध हैं। इनका उपयोग ड्रिप माध्यम से किया जा सकता है। इस तकनीक के जरिए आसानी से फसलों को सही मात्रा में सही समय पर उर्वरकों के माध्यम से पोषक तत्व मिल जाते हैं। फसलों की गुणवत्ता और उपज दोनों बेहतर होती हैं। पानी, ऊर्जा और मज़दूरी की बचत कर उन्नत सिंचाई करने वाली ऑटोमेटिक ड्रिप इरिगेशन और फर्टिगेशन सिस्टम यूनिट का खर्च 7 से 8 लाख रुपए पड़ता है ऐसी कई कंपनियां हैं, जो इसका निर्माण करती हैं। किसान इस सिस्टम को खरीदकर अपनी खेती में प्रयोग कर भरपूर फायदा ले सकते हैं। इस पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी की सुविधा भी है। सब्सिडी को अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के कृषि विभाग और उद्यान विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

कंप्यूटर से होता है संचालित

ऑटोमेटिक ड्रिप इरिगेशन और फर्टिगेशन सिस्टम कंप्यूटर से संचालित किया जाता है। इस सिस्टम के साथ वॉल्व लगे होते हैं। वॉल्व के जरिए कितने समय तक, कितना पानी देना है, इसकी सेटिंग कंम्प्यूटर से कर दी जाती है। किसान बिना फार्म पर रहे भी पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। इंटरनेट के जरिए इसको कहीं से भी संचालित किया जा सकता है। ऑटोमेटिक ड्रिप इरिगेशन और फर्टिगेशन सिस्टम में मेन पाइप लगा होता है। इसमें पानी तालाब या जमीन से आता है। फिर पानी फिल्टर टैंक से होते हुए आउटलेट पाइपों में जाता है। ये पाइप फील्ड के अनुसार लगे होते हैं। इसी फील्ड पाइप पर वॉल्व लगे होते हैं, जो कंट्रोलर से कंट्रोल होता है। कंट्रोलर से किस खेत और किस फसल को कितना और कब पानी देना है, इस बात का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए कंट्रोलर में प्रोगाम सेट कर दिया जाता है, जिससे वॉल्व को ऑटोमेटिक तरीके से संचालित किया जाता है। फसल को जब सिंचाई की जरूरत होती है तो ऑटोमेटिक तरीके से मशीन चालू हो जाती है। फसलों की जरूरत के हिसाब से खेत की सिंचाई हो जाती है। सिंचाई का कार्य होने के बाद मशीन ऑटोमेटिक बंद भी हो जाती है। फसल, पानी और फर्टिलाइजर के अनुसार सिस्टम ऑटोमेटिक खुलता और बंद होता है।

आईसीएआर द्वारा सुझाए गए 5 उपकरण

बोवनी से लेकर खाद डालने और निराई-गुड़ाई के कृषि उपकरण उपलब्ध

जागत गांव हमार। भोपाल

खेती के काम में समय, श्रम और पैसों की बचत के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। इससे काम कम समय में अधिक कुशलता से होता है, जिससे किसानों की लागत कम होती है। बीज बोने से लेकर खाद डालने और निराई-गुड़ाई के लिए भी कई कृषि उपकरण उपलब्ध हैं। आईसीएआर द्वारा सुझाए गए कुछ खास कृषि उपकरणों के बारे में हम आपको इस लेख में बताएंगे, जो किसानों के लिए खेती के कामों को सुगम बना रहे हैं।

1. स्वचालित पावर वीडर-

कतार वाली फसलों, बागवानी और सब्जियों की फसलों में निराई और बीज बोने की तैयारी करने के लिए यह मशीन उपयोगी है। इसमें पावर टिलर चेसिस, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, एमएस व्हील, एक फ्रेम और एक रोटरी टिलर और 4.1 किलोवाट का डीजल इंजन होता है। इंजन से पावर को बेल्ट और चेन की मदद से रोटरी तक और गियर ट्रेन के माध्यम से जमीन के पहियों तक पहुंचाया जाता है। गहराई एडजस्ट करने के लिए पावर टिलर के दोनों किनारों पर दो स्किड्स दिए गए हैं। रोटरी सिस्टम को बिजली से जोड़ने या बंद करने के लिए एक पावर कट-ऑफ डिवाइस भी दिया गया है। इसकी कीमत करीब 40 लाख है। खुरपी द्वारा हाथ से निराई की तुलना में यह मशीन 90 फीसदी तक समय की बचत करती है। साथ ही 30 फीसदी तक निराई की लागत बचाती है।

2. पावर वीडर फॉर लो लैंड राइस

तमिलनाडु कृषि विवि ने मैसर्स प्रीमियर पावर इक्विपमेंट एंड प्रॉडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से दो कतार वाला पावर वीडर विकसित किया। यह सभी तरह की मिट्टी में कतार में बोए गए धान और एसआरआई विधि से बोए गए धान में समय-समय पर निराई-गुड़ाई करने के लिए उपयुक्त है। यह स्वचालित, छोटा और हल्का पावर वीडर है। इसका वजन 17 किलो है। इसमें 1.30 किलोवॉट का इंजन, फ्लोट और रोटरी कटिंग ब्लेड लगे हुए हैं। दोनों तरफ चार हाई स्पीड रोटेटिंग ब्लेड (300 आरपीएम) है, जो एक बार में दो कतारों की निराई करते हैं। छोटा और हल्का होने के कारण यह फसल की कतारों के बीच तेजी से चल सकता है। पावर वीडर के संचालन की औसत गति लगभग 30 मीटर/मिनट है।

3. ट्रैक्टर माउंटेड 3-रो रोटरी वीडर

इस 3-रो रोटरी वीडर को ट्रैक्टर के सतह जोड़कर ऑपरेट किया जाता है। इस ट्रैक्टर माउंटेड 3-रो रोटरी वीडर को लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विवि ने डिजाइन और विकसित किया है। इसमें एक मुख्य फ्रेम, गियरबॉक्स, तीन रोटरी वीडिंग ब्लेड असेंबली, गियरबॉक्स से रोटरी असेंबली में पावर सप्लाई के लिए 40 मिलीमीटर वर्ग शाफ्ट, स्प्रोकेट और चेन का एक सेट है। यह पंक्ति-से-पंक्ति की दूरी को 675 से 1165 मिलीलीटर तक एडजस्ट करने की सुविधा देता है। मशीन की निराई कुशलता 83-87 फीसदी है। यह 0.24 हेक्टेयर/घंटे के हिसाब से काम करती है। इस मशीन की कीमत करीब 60 हजार रुपए है।

4. उर्वरक बैंड प्लेसमेंट सह अर्थिंग अप मशीन

ट्रैक्टर से चलने वाली उर्वरक बैंड प्लेसमेंट सह अर्थिंग अप मशीन को उत्तराखंड स्थित पंतनगर यूनिवर्सिटी ने विकसित किया है। यह मशीन 0.50 मीटर से ज्यादा पंक्ति से पंक्ति की दूरी होने पर मक्का, गन्ना, आलू आदि फसलों में खाद डालने, मिट्टी चढ़ाने और खरपतवारों को काटने के लिए उपयुक्त है। प्रति हेक्टेयर यूरिया/खाद डालने की दर 60 से 250 किलो के बीच है। यह प्रति घंटा 0.56 हेक्टेयर क्षमता के साथ कार्य कर सकती है। मशीन की कीमत लगभग 50 हजार है। परंपरागत विधि की तुलना में इस विधि में उर्वरक, समय और श्रम की काफी बचत होती है।

5. रतून गन्ना के लिए ट्रैक्टर संचालित उर्वरक डिबलर

तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयंबटूर ने खाद डालने के लिए एक ट्रैक्टर से चलने वाला उर्वरक डिब्बलर विकसित किया है। इस उपकरण की कीमत करीब 45 हजार रुपए है और ऑपरेटिंग कैपेसिटी 0.2 हेक्टेयर/घंटा है। पारंपरिक तरीके की तुलना में इस उपकरण के इस्तेमाल से 60 प्रतिशत तक पैसों की बचत होती है। प्रति हेक्टेयर संचालन लगात 1550 रुपए पड़ती है।

मत्स्य विशेषज्ञ मुकेश कुमार सांरग ने दी पूरी जानकारी

बायोफ्लॉक तकनीक से कम जगह में बंपर मछली उत्पादन

जागत गांव हमार। भोपाल

अगर आप मछली पालन को व्यावसायिक रूप से शुरू करना चाहते हैं तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बड़े क्षेत्र में तालाब बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मछली पालन की नई तकनीक बायोफ्लॉक को अपनाकर बहुत कम जगह में मछली का बंपर उत्पादन लेकर अच्छी आय कमा सकते हैं। क्या है बायोफ्लॉक तकनीक इस बारे में **'जागत गांव हमार'** ने उत्तर प्रदेश स्थित मत्स्य विभाग विंध्याचल मंडल मिर्जापुर के उपनिदेशक मुकेश कुमार सांरग से खास बातचीत की। मत्स्य विशेषज्ञ मुकेश कुमार सांरग ने बताया कि बायोफ्लॉक तकनीक के तहत टैंकों में मछली पाली जाती है। इसमें तालाब खोदने की जरूरत नहीं पड़ती। जिनके पास कम जगह है, वो बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन कर सकते हैं। इस तकनीक में पानी की बचत के साथ-साथ मछलियों के फीड यानी कि आहार की भी बचत होती है। मछली जो भी खाती है उसका 75 फीसदी वेस्ट के रूप में बाहर निकालती है। ये वेस्ट पानी के अंदर ही रहता है। इसी वेस्ट को शुद्ध करने के लिए बायोफ्लॉक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। मछलियां जो वेस्ट निकालती हैं, उसको बैक्टीरिया के द्वारा प्यूरीफाई किया जाता है। यह बैक्टीरिया मछली के मल को प्रोटीन में बदल देता है। मछलियां इस प्रोटीन को खा लेती हैं। इस तरह से 1/3 मछली फीड की बचत होती है। अगर तालाब में मछली फीड की तीन बोरी खर्च होती हैं तो इस तकनीक के इस्तेमाल से दो बोरी ही खर्च होंगी।

कम जगह में अधिक उत्पादन

मत्स्य एक्सपर्ट मुकेश कुमार सांरग आगे बताते हैं कि अगर कोई 10 हजार लीटर के एक बायोफ्लॉक टैंक में मछली पालन करता है तो उसको पांच महीने में ही 500 किलो तक मछली का उत्पादन मिल जाएगा। जबकि सामान्य तकनीक से मछली का इतना उत्पादन लेने के लिए एक हेक्टेयर के क्षेत्रफल के तालाब की जरूरत पड़ती है। उन्होंने बताया कि बायोफ्लॉक तकनीक में चार महीने में केवल एक ही बार पानी भरा जाता है। टैंक में गंदगी जमा होने पर केवल दस प्रतिशत पानी निकालकर दोबारा साफ करके रखा जा सकता है। इस तकनीक में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इसमें 24 घंटे बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही इसमें जो बैक्टीरिया पलता है वो ऐरोबिक बैक्टीरिया है, जिसको 24 घंटे हवा की जरुरत होती है तभी वह जीवित रहता है।

बायोफ्लॉक टैंक में 30 हजार का खर्च

मुकेश कुमार सांरग ने बायोफ्लॉक टैंक बनवाने में लगने वाली लागत के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि लागत इस बात पर निर्भर करती है कि किस साइज का बायोफ्लॉक टैंक बनवा रहे हैं। टैंक का साइज जितना बड़ा होगा उसमे पलने वाली मछलियों का विकास भी उतना ही अच्छा होगा। बायोफ्लॉक का 10 हजार लीटर क्षमता के टैंक को बनाने में लगभग 28 से 30 हजार रुपए का खर्चा आता है। इसमें उपकरण और लेबर चार्ज शामिल है। सिर्फ एक बार सीमेंट या प्लास्टिक टैंक बनाने में खर्च आता है। उसके बाद बेहतर प्रबंधन करने पर छह महीने के बाद मछलियों का उत्पादन मिलना शूरू हो जाता है। इस तकनीक में एक लाख खर्च कर हर साल दो से तीन लाख की कमाई कर सकते हैं।

पाली जाने वाली मछली की प्रजातियां

मत्स्य विशेषज्ञ मुकेश कुमार सांरग ने बताया कि बायोफ्लॉक तकनीक में एक एयरेटर की जरूरत होती है। ये पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने में सहायक होता है। टैंकों में पानी की सप्लाई के लिए एक इनलेट पाइप लगा होता है। गंदे पानी को निकालने के लिए एक आउटलेट पाइप टैंक के निचले हिस्से में लगा होता है। टैंक में इनलेट, आउटलेट और एयरेटर सिस्टम को चलाने के लिए 2 एचपी पॉवर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। उन्होंने बताया कि बायोफ्लॉक तकनीक में तिलापिया, मांगूर, केवो, कामनकार्प जैसी मछलियों का पालन किया जा सकता है।

बॉयोफ्लाक टैंक बनवाने पर सब्सिडी

मत्स्य एक्सपर्ट मुकेश कुमार सारंग ने जानकरी दी कि इस तकनीक को अपने घर के आसपास या खेतों में 250 स्कवायर फीट से लेकर 1500 स्क्वायर फीट के सीमेंट टैंक बनवाकर मछली पालन शुरू कर लाभ कमा सकते हैं। बॉयोफ्लाक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सरकार सब्सिडी भी दे रही हैं। अगर कोई आठ टैंकों वाला बॉयोफ्लाक का प्रोजेक्ट लगाता है तो उसे लगभग साढ़े सात लाख का खर्चा आएगा। प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत एससी-एसटी महिलाओं के लिए 60 फीसदी सब्सिडी और अन्य के लिए 40 फीसदी की सब्सिडी प्रस्तावित है।

बुंदेलखंड में मशरूम की खेती से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

टीकमगढ़। कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ में मशरूम उत्पादन पर बुंदेलखंड महिला मशरूम उत्पादन स्व-सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ.बीएस किरार द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को मशरूम की उपयोगता एवं उसके महत्व के विषय में जानकारी प्रदान की गयी। मशरूम उच्च कोटि प्रोटीन, विटामिन, खाद्य रेशो, खनिज लवणों का अच्छा स्रोत है। यह फसल अवशेषों को गुणवता वाले प्रोटीन 21-37 प्रतिशत शुष्क आधारित भार में पायी जाती है। मशरूम हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, कब्ज, मधुमेह रोगियों के लिए सर्वोतम आहार हैं। इसकी उपयोगिता के कारण इसकी व्यवसायिक खेती दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। वैज्ञानिक डॉ. आरके प्रजापति द्वारा आयस्टर मशरूम के व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी और उसमे समस्याओं के निदान एवं सावधानियों के विषय में जानकारी प्रदान की। मशरूम उत्पादन विशेषकर ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार युवाओं और महिलाओं के लिए अतरिक्त आय और स्वरोजगार का स्त्रोत विकसित होगा। केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. सुनील कुमार जाटव द्वारा मशरूम के विभिन्न पदार्थों का संरक्षण एवं प्रसंस्करण जेसे की अचार, खीर, मुरब्बा, पाउडर केसे बनाएं इत्यादि पर जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में केंद्र के वैज्ञानिक डॉ .एसके सिंह, डॉ. यूएसधाकड़, जयपाल छिगाराह एवं हंसनाथ खान ने तकनीक पर विचार व्यक्त किए।

सभी छोटे चेक डैम और पानी के अन्य स्रोत पड़े हुए हैं खाली

बाणसागर बांध खाली फिर भी यूपी और बिहार को दे रहे पानी

जागत गांव हमार। शहडोल

जिला मुख्यालय से तकरीबन 95 किलोमीटर दूर स्थित बाणसागर बांध अपनी जल भराव क्षमता से 8 मीटर खाली है इसके बावजूद उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों को लगातार पानी यहां से भेजा जा रहा है। शहडोल में मानसून की अच्छी बारिश अब तक नहीं हो पाई है जिसके कारण बाणसागर बांध खाली है। जिले के तालाब भी सूखे पड़े हैं और अच्छी बारिश का इंतजार हो रहा है। जिले की नदियों में भी पानी का प्रवाह अवरुद्ध है जिसके कारण सभी छोटे चेक डैम और पानी के अन्य स्रोत खाली पड़े हुए हैं। रविवार की सुबह जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके मुताबिक बाणसागर बांध में इस समय 334.24 मीटर पानी भरा हुआ है, जबकि बांध की भराव क्षमता 341.64 मीटर है। इस समय बांध 41.97 फीसदी भरा हुआ है। पिछले साल बाणसागर बांध में 333.97 मीटर पानी भर चुका था।

उत्तर प्रदेश और बिहार को दिया जा रहा पानी

बाणसागर बांध से उत्तर प्रदेश और बिहार को लगातार पानी भेजा जा रहा है। मिली रिपोर्ट के मुताबिक बिहार को प्रतिदिन 196 क्यूमेक्स और उत्तर प्रदेश को 30 क्यूमेक्स पानी प्रतिदिन बांध से निकाला जा रहा है। इस तरह से प्रतिदिन 6 सेंटीमीटर पानी प्रतिदिन बांध से कम हो रहा है। गौरतलब है कि जिले में अब तक 92.50 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यह बांध की भराव के लिए काफी कम है।

ग्वालियर में तिघरा बांध 50 प्रतिशत खाली, बारिश पर टिकी आस

इधर, ग्वालियर में गर्मियों के मौसम में तिघरा बांध को भरने के लिए करीब एक माह से पेहसारी बांध से छोड़ा जा रहा पानी बंद कर दिया गया है। तिघरा को भरते-भरते अपर ककैटो, ककैटो और पेहसारी तीनों बांध खाली हो गए हैं। वहीं तिघरा बांध अब भी इस समय 50 प्रतिशत खाली पड़ा हुआ है। पेहसारी बांध के अंदर 247 एमसीएफटी पानी बचा है। अमृत योजना के शुरू होने के कारण ग्वालियर शहर में प्रतिदिन 3 एमसीएफटी पानी की सप्लाई बढ़ गई हैं। पहले ग्वालियर में प्रतिदिन 8 से 9 एमसीएफटी पानी की सप्लाई होती थी, जबकि अब शहर में 12 एमसीएफटी पानी की सप्लाई हो रही है। इसके कारण तिघरा बांध भी लगातार खाली हो रहा है। दूसरी तरफ भीषण गर्मी के कारण बांध के अंदर तेजी से पानी का वाष्पीकरण हो रहा है। तिघरा में इस समय 2100 एमसीएफटी पानी ही बचा है। तिघरा के जलस्तर को बढ़ाने के लिए जल संसाधन विभाग ने गर्मियों के मौसम में अपर ककैटो, ककैटो और पेहसारी बांध से पानी की सप्लाई करना प्रारंभ किया था। तिघरा को भरने के लिए अपर ककैटो बांध को पूरा खाली कर उसका पानी ककैटो बांध में लाया गया था, इसके बाद ककैटो बांध से पानी को नहर के जरिए पेहसारी बांध में लाया गया। पेहसारी बांध से निकली नहर के जरिए पानी को सांक नदी में छोड़ा गया, जहां से पानी तिघरा बांध तक पहुंचाया जा रहा है। वर्तमान समय में अपर ककैटो बांध पूरी तरह से खाली हो चुका है। जबकि ककैटो बांध का जलस्तर पेहसारी बांध में छोड़ी जाने वाली नहर से नीचे आ चुका है। तिघरा बांध इस समय 50 प्रतिशत से कम भरा हुआ है। इसके चलते सितंबर 2022 के मध्य तक पानी की सप्लाई ओर की जा सकती है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की योजना है कि बारिश के मौसम में इन सभी बांधों को फिर से भर दिया जाएगा। जिससे शहर में पेयजल एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता पूरी हो सकेगी।

पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए अब जरूरी है ई केवाईसी कराना

अधिकारी भी किसानों को ई-केवाईसी कराने के लिए जागरू कर रहे

ई-केवाईसी कराने में श्योपुर 26वें नंबर पर, अटक सकती है 45 हजार किसानों की 'सम्मान निधि'

खेम राज मौर्य। शिवपुरी/श्योपुर

जिले के 45 हजार से ज्यादा किसानों की पीएम किसान सम्मान निधि अटक सकती है। क्योंकि इन किसानों के द्वारा अभी तक ई-केवाईसी सत्यापन नहीं कराया गया है। किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी कराने की अनिवार्यता होने के बाद भी जिले के किसान ई-केवाईसी कराने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए श्योपुर का नाम पूरे प्रदेश में 26वें नंबर पर है, इससे श्योपुर प्रदेश में फिसड्डी साबित हो रहा है।

दरअसल, जिले में 93 हजार से ज्यादा किसान पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ रहे हैं। अब सरकार ने इस योजना का लाभ जारी रखने के लिए किसानों के लिए ई-केवाईसी सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया है। पीएम किसान पोर्टल की नई व्यवस्था के मुताबिक अब किसानों को पोर्टल पर जाकर अपना ई-केवाईसी (जरूरी जानकारी) भरकर सबमिट करना होगा, जिसके बाद ही अब किसान सम्मान निधि का लाभ अपने बैंक खातों में पा सकेंगे। सत्यापन न कराने वाले किसानों को सरकार इस योजना के लाभ से वंचित भी कर सकती है। इसलिए किसान ई-केवाईसी कराने में लग गए है। वहीं संबंधित विभागीय अधिकारी भी किसानों को ई-केवाईसी कराने के लिए जागरू कर रहे है। इसके बाद भी किसान इस दिशा में जागरूकता नहीं दिखा रहे हैं।

47 हजार से ज्यादा किसानों ने कराया सत्यापन

प्रधानमंत्री किसान पोर्टल पर जिले के 93 हजार से ज्यादा किसान पंजीकृत हैं। जिन्हें 6 हजार के रुपए के रूप में पीएम किसान सम्मान निधि और 4 हजार के रूप में सीएम किसान सम्मान निधि दी जा रही है। बताया गया है कि 93 हजार से ज्यादा किसानों में से 47 हजार से ज्यादा किसानों ने ई-केवाईसी सत्यापन करा लिया है। जबकि 45 हजार 776 किसान अभी यह सत्यापन नहीं करा पाए हैं।

कैसे कराएं ई-केवाईसी

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पीएम किसान में रजिस्टर्ड किसान जो अभी तक ई-केवाईसी नहीं करा सके हैं उनके लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 तक बढ़ाई गई है। पीएम किसान पोर्टल पर किसान ई-केवाईसी अपडेट करने के लिए स्वयं ही अपने मोबाइल पर कर सकते हैं या किसानों को इसमें किसी प्रकार की असुविधा होती है तो नजदीकी डिजिटल सेवा केन्द्र इसका सत्यापन करवा सकते हैं।

टॉप-टेन जिलो में संभाग के 5 जिले शामिल

पिछले सप्ताह जारी हुई प्रदेश स्तरीय टॉपटेन सूची में श्योपुर जिले का नाम नहीं है। लेकिन ग्वालियर-चंबल संभाग के पांच जिले में टॉप-टेन सूची में शामिल हैं। बताया गया है कि बालाघाट जिला पहले स्थान पर है। जबकि दूसरे स्थान पर अशोकनगर, तीसरे स्थान पर शिवपुरी, छटवें स्थान पर दतिया, नौवें स्थान पर मुरैना और दसवें स्थान पर भिंड जिला है।

कैसे स्वच्छ बने शिवपुरी: ट्रेंचिंग ग्राउंड पर खाद प्रसंस्करण यूनिट हो रही कबाड़

शिवपुरी। शिवपुरी में बड़ौदी पर बनाए गए ट्रेंचिंग ग्राउंड पर शहर भर के कचरे से खाद बनाकर नगर पालिका की सालाना आमदनी में लाखों की आमदनी बढ़ाने के दावे के साथ यहां प्रोसेसिंग यूनिट तैयार की गई। कुछ समय पहले ही कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह को को भी यहां की विजिट कराकर बड़ी-बड़ी बातें की गईं। नपा के इस ट्रेंचिंग ग्राउंड की जमीनी हकीकत और खाद बनाने की प्रोसेस को समझने के लिए ट्रेंचिंग ग्राउंड पर जाकर जमीनी हकीकत को जानने का प्रयास किया, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। दूसरे दिन एक बार फिर ट्रेंचिंग ग्राउंड का भ्रमण किया और इस बार भी हालात जस के तस थे। ट्रेंचिंग ग्राउंड में लगे कचरे के ढेर में से मवेशी प्लास्टिक खाते मिले। पास की ही बस्ती में रहने वाले कई छोटे-छोटे बच्चे कचरे के ढेर में खेलते और कचरे में से प्लास्टिक बीनते हुए मिले। स्टाफ के नाम पर वहां कोई नहीं था, जो इन मवेशियों और बच्चों को संक्रमण से दूर करने के लिए तैनात किया गया है। यहां खाद लगाने के लिए जो प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई है, वह धीरे-धीरे कबाड़ होने की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में अगर यह कहा जाए कि खाद बनाने के लिए ट्रेंचिंग ग्राउंड पर खर्च किए गए लाखों रुपए हुए खाक हो गए हैं तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां न तो कचरे का कोई प्रथक्करण होते हुए नजर आया और न ही उसके कोई प्रमाण मौके पर मौजूद थे। इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यहां जो स्टाफ 24 घंटे के लिए तैनात किया गया है, वह सिर्फ कागजों में ही ड्यूटी कर रहा होगा। इस मामले में जब जिम्मेदार अधिकारियों को फोन लगाया तो उनका मोबाइल आउट आफ कवरेज एरिया बता रहा था। नपा से जुड़े विश्वसनीय सूत्रों की मानें तो यह सब कुछ स्वच्छता सर्वेक्षण में अंक पाने के लिए किया गया था, ताकि स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम व्यवस्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड और वहां लगी खाद बनाने की प्रोसेस यूनिट को देखकर नपा को स्वच्छता सर्वेक्षण में अंक दे दे। स्वच्छता सर्वेक्षण के उपरांत किसी भी जिम्मेदार ने इस ओर मुड़ कर भी नहीं देखा होगा।

-नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल में 2 लाख हेक्टेयर में मोटे अनाज की बोवनी का लक्ष्य

खरीफ मौसम में मक्का के अलावा अन्य मोटे अनाज की बोवनी पर जोर दिया

मोटे अनाज के साथ कोदो कुटकी की बोवनी भी कर रहे अन्नदाता

-संभाग में जहां 1 लाख 95 हजार हेक्टेयर में मक्का की बोवनी की जा रही

नर्मदापुरम। नर्मदापुरम संभाग के तीनों जिले नर्मदापुरम, हरदा व बैतूल में कुल मिलाकर दो लाख हेक्टेयर में मोटे अनाज की बोवनी का लक्ष्य तय किया गया है। खरीफ मौसम में मक्का के अलावा अन्य मोटे अनाज की बोवनी पर जोर दिया जा रहा है। जिसके तहत संभाग में जहां 1 लाख 95 हजार हेक्टेयर में मक्का की बोवनी की जा रही है। 4 हजार 10 हेक्टेयर में ज्वार तथा 62 हेक्टेयर में कोदो- कुटकी की खेती का लक्ष्य तय किया गया है। कृषि विभाग से मिल रही जानकारी के अनुसार इस बार नर्मदापुरम जिले में 40 हजार हेक्टेयर में मक्का, 2 हजार में ज्वार,2 हेक्टेयर में कोदो कुटकी लगाई जाना तय हुआ है। हरदा में 20 हजार में मक्का,10 हेक्टेयर में ज्वार,10 हेक्टेयर में कोदो कुटकी इसी प्रकार बैतूल जिले में 1 लाख 36 हजार हेक्टेयर में मक्का,2 हजार में ज्वार तथा 50 हेक्टेयर में कोदो कुटकी की फसल लगाई जाने की तैयारी की जा रही है।

सेहत के लिए भी फायदेमंद

वैद्य चंद्रनारायण महलवार का कहना है कि ठंड के मौसम में मोटे अनाज का सेवन करने से सेहत बनती है। कई शौकीन लोग हर वर्ष मोटे अनाज की खरीदी करते हैं। इसी कारण शहर के हाट बाजार में मोटे अनाजों की अच्छी खासी बिक्री होती है। शासन के द्वारा भी समर्थन मूल्य पर इन मोटे अनाजों को खरीदा जाता है।

किसानों का बढ़ रहा रुझान

किसान ब्रजेश मिश्रा ने बताया कि हर तरह के अनाज का अपना महत्व है। हमारी कोशिश रहती है कि खेत में तरह-तरह के अनाज की पैदावार की जाए। मक्का और कुछ भूमि पर ज्वार भी लगाते हैं। कोदो कुटकी की पैदावार होती नहीं है इसलिए नहीं बोते हैं लेकिन ठंड के मौसम में बाजार से खरीदते हैं। कृषि विभाग के वरिष्ठ कृषि अधिकारी किशोर उमरे ने कहा कि जिले में मोटे अनाज की बोवनी की तरफ भी किसानों का रूझान है कुछ मात्रा में ज्वार के साथ कोदे कुटकी की भी खेती की जा रही है।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
गिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पता:- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, ज़ोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)